जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 243 प्रभात कोटा, मंगलवार 17 जून, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

इज़रायल का ''आयरन डोम'' डिफैंस सिस्टम ईरान के ''मल्टीलेयर्ड'' हवाई हमलों के सामने असफल रहा

''आयरन डोम'' की इस पराजय से भारत में अचानक ''खतरे की घंटियाँ'' बज उठीं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जून। ईरान द्वारा आयरन डोम में सेंध लगाना इस इज़राइली रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े करता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में, जब उस पर तकनीकी रूप से सक्षम और समन्वित हमले किए जाएं। यह पहला अवसर था, जब आयरन डोम स्पष्ट रूप से व्याकुल सा नज़र आया। ईरान का सही तालमेल से किया गया हमला, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे, इसके लेयर्ड डिफैन्स को चकमा देकर तेल अवीव के किरिया कंपाउंड सहित, कई शहरी और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल रहे।

कई सैन्य विश्लेषकों ने इस क्षण को एक ''रणनीतिक परिवर्तन बिंदु'' कहा है, अर्थात वह समय, जब किसी सिस्टम या संगठन को ऐसे बदलाव का सामाना करना पड़े, जो उसके भविष्य की दिशा व सफलता को प्रभावित कर दे। पर इसका मतलब यह नहीं कि आयरन डोम पूरी तरह विफल हो गया, इसने अब भी बड़ी संख्या में हमलों को विफल किया, लेकिन इसकी एक प्रमुख कमजोरी उजागर हो गई है, वो यह कि यह प्रणाली मूलतः छोटी रेंज के, कम मात्रा में होने वाले रॉकेट हमलों से निपटने के लिए बनाई गई थी, जो कि हमास और हिज़्बुल्लाह द्वारा किये जाते हैं, न कि ईरान जैसे बड़े राष्ट्र द्वारा किए जा रहे उच्च मात्रा और बहु-दिशात्मक हमलों से।

भारत, ने इज़राइल से कई रक्षा प्रणालियाँ, जैसे सतह से हवा में मार करने वाली, मिसाइल प्रणाली बराक, एयर डिफेंस सिस्टम स्पायडर, हेरोन यूएवी, हारोप लुटेरिंग म्यूनिशन और फाल्कन एडब्ल्यूसीएस खरीदी हैं, यह एक गंभीर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा करता है। भारत के समक्ष भी इज़राइल की तरह जटिल सुरक्षा खतरे हैं, जिनमें परमाणु संपन्न पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तथा कई अतिवादी समूह शामिल हैं। यह सेंध दर्शाती है कि इज़राइली प्रणालियाँ, भले ही ''एसिमेट्रिकल'' (असंयमित या असंतुलित) युद्ध में प्रभावी रही हों, परंतु तकनीकी रूप से सक्षम शत्रु के साथ पूर्ण युद्ध में वे पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकतीं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत ने सदा इज़रायल के ''आयरन डोम'' सिस्टम पर पूरा भरोसा कर, इस सिस्टम के कई अवतार, जैसे, बराक सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफैंस सिस्टम, आदि, खरीदे थे तथा शत्रु देश के हवाई हमले को घटिया मानते हुए चैन की नींद सो रहा था।
- ''आयरन डोम'' में छेद होने से यह भी साबित हुआ कि किसी भी ''डिफैंस सिस्टम'' पर पूरा भरोसा करके निश्चिंत हो जाना, कोई अक्लमंदी का काम नहीं है।
- प्रभावशाली सुरक्षा के लिए आयातित डिफैंस सिस्टम, (जैसे आयरन डोम) चाहे कहीं से, विदेश से, इज़रायल, अमेरिका, रूस आदि से आयातित हो, उसका स्वदेशी ''आर.एण्ड डी.'' वैपन सिस्टम से समन्वय होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, डी.आर.डी.ओ. द्वारा भारत में विकसित आकाश व क्यू.आर.एस.ए.एम. डिफैंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमले, जिसमें लड़ाकू विमान व ड्रोन भारी संख्या में शामिल थे, को नाकाम किया था।
- निरंतर आर.एण्ड डी. ही भारत को कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई

जयपुर, 16 जून। आरपीएससी की ओर से मंगलवार से शुरु होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा-2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। आकाश मिश्रा व दो अन्य ने याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की गुहार की है। याचिकाकर्ताओं ने अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा के समक्ष प्रकरण की सुनवाई सोमवार को ही करने की गुहार की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी से 17 और 18 जुलाई को आरएएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कर रही है, जबकि अभी तक आरएएस भर्ती-2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वर्तमान में, इस परीक्षा के साक्षात्कार चल रहे हैं। ऐसे में, बीते साल की इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की सिफारिश कर चुके हैं। इस आधार पर परीक्षा स्थगित होने के निर्णय की प्रतीक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- याचिका में कहा गया है कि 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसके पूरे होने तक 2024 की परीक्षा स्थगित की जाए।

ट्रंप, इज़रायल-ईरान के बीच में भी युद्ध विराम कराने को लालायित

पर, ईरान कतर व ओमान को मध्यस्थ बनाना चाहता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वह ईरान और इज़रायल के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के अपने प्रयासों को लेकर आशावादी हैं, ठीक उसी तरह, जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रयास किए थे। इस बीच, ईरान ने ओमान और कतर जैसे क्षेत्रीय देशों से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है।

ईरान और इज़रायल के बीच सैन्य टकराव शुरू होने के लगभग 48 घंटे के भीतर, सीमित लेकिन केंद्रित कूटनीतिक प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य इस टकराव को और बिगड़ने से रोकना और अंततः कोई समाधान निकालना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की,

''इज़रायल और ईरान के बीच जल्दी ही शांति होगी'' और दोनों देशों को ''समझौता करना चाहिए, और वे करेंगे भी।''अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ''इस समय बहुत सारे कॉल और बैठकें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन मुझे कभी श्रेय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लोग तो समझते हैं। मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे।''

इस बीच, जैसे ही इज़रायल ने ईरान पर अपने हमलों का दायरा बढ़ाया, तेहरान ने कतर और ओमान से राजनयिक माध्यमों के जरिए संपर्क किया है और क्षेत्रीय मध्यस्थों से हस्तक्षेप कर बातचीत फिर से शुरु कराने का अनुरोध किया है। यह जानकारी रविवार को कई इज़रायली मीडिया संस्थानों ने इज़रायली सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। उन्हीं इज़राइली सरकारी सूत्रों के अनुसार, ईरान ने कतर और ओमान से अमेरिका तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है कि वह संघर्षविराम पर बातचीत के लिए तैयार है, या फिर अमेरिका इज़रायल को हमला रोकने के लिए कहे। वहीं, सऊदी अरब भी कथित तौर पर इस संघर्ष को शांत करने के लिए गुप्त कूटनीति में सक्रिय है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जैसा कि विदित है, ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच ''सीज़फायर'' करवाया था।
- सऊदी अरब भी परोक्ष रूप से मध्यस्थता के प्रयास में जुड़ना चाह रहा है।
- ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी विदेशी राजदूतों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ''नेगोशिएटिंग टेबल'' पर आकर, जैसा कि ट्रंप ने कहा है, अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों पर नियंत्रण करने को तैयार है। मगर, अमेरिका को इज़रायल के हवाई हमलों को भी रोकना पड़ेगा।

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

सोनिया गांधी को रविवार की रात पेट की तकलीफ के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जून। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रविवार रात पेट संबंधी समस्या के चलते सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले, उन्होंने शिमला में अपनी नियमित मैडिकल जाँच करवाई थी।

सर गंगा राम अस्पताल के चयरमैन डॉ. अजय स्वरुप ने इस बात की पुष्टि की तथा कहा, ''श्रीमती सोनिया गांधी को रात 9:00 बजे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजे विभाग में पेट की समस्या के कारण भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है।''

अठहत्तर वर्षीय वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, जो अब भी कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में चिकित्सीय सलाह ली थी। 7 जून को उन्हें मामूली अस्वस्थता के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज और अस्पताल (आईजीएमसी) ले जाया गया था, जहाँ उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने उस समय स्पष्ट किया था कि उन्हें एहतियात के तौर पर आईजीएमसी लाया गया था।

उन्होंने कहा, वे कुछ मामूली समस्याओं के कारण, नियमित जाँच के लिए आई थीं। डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और सब कुछ सामान्य पाया।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सर गंगाराम अस्पताल के चैयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी को रात में सर्जिकल गैसट्रोएन्टेरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।
- गत दिनों जब सोनिया गांधी शिमला में थीं तब भी उनकी तबियत कुछ बिगड़ गई थी और उन्हें जाँच के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब उनका ब्लड प्रैशर बढ़ा हुआ पाया गया था।

मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हुई

नयी दिल्ली, 16 जून। देश में मई 2025 में बेरोजगारी की दर बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो गयी है।

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को यहां जारी श्रम बल सर्वेक्षण - मई 2025 में कहा कि अप्रैल 2025 में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत रही थी जो मई में बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो गयी है।

मंत्रालय ने बताया कि संबंधित सर्वेक्षण में 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल किया जाता है। मई 2025 के सर्वेक्षण के लिए 7511 गांवों और उप नगरों को शामिल किया गया। इसमें 89 हजार 372 परिवार रहे। कुल तीन लाख 79 हजार 600 लोगों से बात की गयी।

- सोमवार को जारी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, अप्रेल में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत थी जो बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई है।

1,500 कश्मीरी विद्यार्थी तेहरान के ''वॉर ज़ोन'' में फंसे हुए है

ये विद्यार्थी, तेहरान में मैडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जून। पश्चिम एशिया में इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच, भारत ने ईरान में फंसे लगभग 1,500 कश्मीरी छात्रों, जिनमें अधिकांश तेहरान और उसके आसपास मैडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक प्रयास शुरू किए हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईरानी सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों के लिए, सुरक्षित निकासी का मार्ग तैयार किया जा रहा है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर निकासी और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुटा है।

इस संकट ने जम्मू-कश्मीर में परिजनों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने सैकड़ों चिंतित अभिभावकों की ओर से भावनात्मक अपील की है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह राजनयिक प्रयास तेज़ करे और हर संभव कदम उठाए, ताकि फंसे हुये युवाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, ''सरकार को तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। ये छात्र घर से दूर, एक युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।''

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकांश छात्र तेहरान के पास स्थित हुज्जत दोस्त अली छात्रावास में रह रहे हैं, छात्रावास ऐसे क्षेत्र के पास स्थित है, जो सैन्य कार्यवाही तेज होने पर प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा छात्रों के अलावा, कई कश्मीरी युवा उद्यमी और व्यापारी भी ईरान में हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षिणक गतिविधियों में लगे हुए हैं।

खासतौर से कश्मीर घाटी के श्रीनगर और अन्य हिस्सों में छात्र परिवारों में गहन चिंता का माहौल है। अभिभावक बता रहे हैं कि वे अपने बच्चों के साथ नियमित संपर्क में हैं, लेकिन संचार में बाधाएं, आपूर्तियों की कमी, और हवाई हमलों की आशंका के चलते छात्रों का भय बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर-निवासी एक अभिभावक मुश्ताक अहमद ने कहा, ''हम हर दिन अपने बेटे से बात करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में डर बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं, कृपया हमारे बच्चों को घर वापस लाएं।''

विदेश मंत्रालय ने इस संकट को स्वीकार किया है और सूत्रों के अनुसार, एक आपातकालीन योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें वहाँ से निकलने के लिये सुरक्षित मार्गों की पहचान, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों की एयरलिफ्टिंग, और क्षेत्र में सहयोगी देशों से समन्वय शामिल हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों के लिए एडवाइज़री भी जारी की है, जिसमें घर के अंदर रहने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने, और दूतावास से लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

चूँकि भू-राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, आने वाले दिन निकासी अभियानों के लिए निर्णायक होंगे। भारत की प्रतिक्रिया न केवल उसकी राजनयिक दक्षता की परीक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत सरकार इन विद्यार्थियों की हिफाज़त व उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत है।
- ईरान ने भी भारत सरकार को विश्वास दिलाया है कि ईरान भी पूरी तरह इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे इन विद्यार्थियों के लिए ''सेफ पैसेज'' की व्यवस्था करें, जिससे वे अपने देश पहुँच सकें।

प्र.मंत्री मोदी को मिला सायप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

निकोसिया, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को यहां साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने राष्ट्रपति महल में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संक्षिप्त समारोह में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'दि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस-3' से अलंकृत किया।इस मौके पर मोदी ने कहा कि यह किसी नरेन्द्र मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और वह भारत के नागरिकों की ओर से पूरी विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं।

- सायप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने ''द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस-3'' से मोदी को अलंकृत किया।

'बार-बार निरुत्साहित करने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता क्यों ग्रीष्मावकाश में सुप्रीम कोर्ट पैरवी करने आते हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के इस आचरण पर भृकुटि तानी व कटाक्ष किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जून। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोर्ट में पेश न हों, ताकि युवा वकीलों को केस लड़ने का अधिक अवसर मिल सके। सोमवार को कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति पर असंतोष जताया।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आज ऐमटैक समूह के प्रवर्तक अरविंद धाम की ओर से अदालत में उपस्थित हुये। धाम ने मनी लॉण्डरिंग केस में अन्तरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, इस प्रकरण में रोहतगी की उपस्थिति के सिलसिले में मौखिक रुप से कहा, ''हमें समझ नहीं आता कि छुट्टियों में वरिष्ठ वकील क्यों पेश हो रहे हैं। इस कोर्ट ने पहले भी इस पर टिप्पणी की है।''

यह पहला अवसर नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों से अवकाश काल में मामलों की बहस से दूर रहने की बात कही है।

जून 2023 में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या जूनियर वकीलों को अपने केस प्रस्तुत करने का, तथा उनमें बहस करने का अवसर मिलना चाहिए।

मई 2024 में भी न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने यही भावना दोहराई थी तथा कहा था कि वरिष्ठ वकीलों को कोर्ट के अवकाश के दौरान, बार के युवा सदस्यों को मुकदमों में बहस करने को अवसर देना चाहिये। जस्टिस करोल ने उस समय कहा था, ''हम चाहते हैं कि युवा बार आगे बढ़े, अवकाश का उद्देश्य भी यही था - युवा अधिवक्ताओं को मंच देना।''

पिछले महीने भी न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने यही राय व्यक्त की थी कि वरिष्ठ वकीलों को गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों व बहस से दूर रहना चाहिए।

हालांकि सोमवार को कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी की उपस्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि वे कोर्ट के अवकाश के दौरान, केस में बहस करने क्यों आये हैं, लेकिन अंततः कोर्ट ने उनकी संक्षिप्त दलीलें सुन लीं।

रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 11 महीनों से हिरासत में हैं और उनकी नियमित जमानत याचिका फरवरी 2025 से दिल्ली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान जब कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की ''वैकेशन बैंच'' में लगता है, यह मौका होता है, युवा वकीलों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बहस करने का, पर, वैकेशन बैंच के समक्ष अगर, फिर वरिष्ठ अधिवक्ता ही आते हैं तो वो युवा वकीलों का ''मौका'' छीनते हैं, जो उचित नहीं है।
- वैकेशन बैंच ने सोमवार को यह टिप्पणी उस समय की, जब, मुकुल रोहतगी अपने क्लाइंट को जमानत दिलवाने के लिए बैंच के सम्मुख पेश हुए।
- बैंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच जमानत के लिए दायर इस अर्ज़ी को पहले ही रद्द कर चुकी है। अतः, अब वरिष्ठ अधिवक्ता वैकेशन बैंच के समक्ष पुनः अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।
- मुकुल रोहतगी ने अपनी जमानत की अर्जी वापस लेने का प्रयास किया।

करोना संक्रमण से 11 मरीजों की मौत

नयी दिल्ली, 16 जून। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान करोना संक्रमण से 11 और मरीजों की मौत होने से इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 108 पहुंच गयी और 119 सक्रिय मामले घटने के साथ कुल सक्रिय मामले 7264 हो गये हैं। इससे पहले रविवार को करोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 7383 थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोराना के संक्रमण से केरल में सात,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि करोना के एक्टिव केसों में मामूली गिरावट आई है। रविवार को करोना के एक्टिव केस 7383 थे जो सोमवार को घटकर 7264 रह गए।